भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 184

उत्तर देने की तारीख: 18.11.2019

शाला दर्पण

184. श्री विजय कुमार दूबेः
श्रीमती संध्या रायः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार केंद्रीय विद्यालयों (केवी) में शाला दर्पण की पहल को लागू कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पहल के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;
(ग) गत तीन वर्षों के दौरान शाला दर्पण योजना के तहत सरकार द्वारा की गई पहल और सामना की गई समस्या का ब्यौरा क्या है;
(घ) शाला दर्पण के पहले चरण की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने राज्य सरकार के स्कूलों में इसी तरह की व्यवस्था शुरू करने के लिए राज्यों को निदेश दिया है और यदि हां, तो इस पर मध्य प्रदेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
(च) क्या सरकार ने मोबाइल फोन के माध्यम से बच्चों की प्रगति की निगरानी करने के लिए माता-पिता को कहीं पर भी जानकारी प्राप्त कराने की कोई व्यवस्था की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क): जी हां। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने 1099 केन्द्रीय विद्यालयों में शाला दर्पण पहल लागू की है।

(ख): शाला दर्पण के उद्देश्य और लक्ष्य निम्नवत हैं।

I. विभिन्न हितधारकों नामत: छात्रों, शिक्षकों, प्रबंधन और अभिभावकों की शैक्षिक और प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एकल एकीकृत मंच का काम करना

II. शैक्षणिक वितरण प्रणाली में सुधार करना जिससे शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार हो

III. हितधारकों अर्थात् माता-पिता आदि की भागीदारी को बढ़ावा देना।

IV. नीतियों, प्रक्रियाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की एकरूपता/मानकीकरण लाना

V. समग्र ई-शासन में सुधार में करना और पारदर्शिता, कुशलता और जबावदेही को बढ़ावा देना

(ग): 1099 केन्द्रीय विद्यालयों में शाला दर्पण का कार्यान्वयन करने के बाद से केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सामने निम्नलिखित समस्याएं आयी हैं:

i. प्रत्येक चरण पर डिलीवरी में 2-16 माह का विलंब

ii. रिमोट सर्वर से कनेक्टिविटी एक प्रमुख मुद्दा है क्योंकि एप्लीकेशन वेब आधारित नहीं है

iii. एप्लीकेशन में अत्यधिक लिंक जिससे उपयोग में भ्रांति होती है

iv. एप्लीकेशन में यूनीकोड समर्थन नहीं था और यह द्विभाषी नहीं है

v. एचआर डैशबोर्ड में लगभग 31 इकाईयों में (केवीएस (मु.)+25 क्षेत्रीय+5 जेडआईईटी) कर्मचारियों के आंकड़ों के समावेशन का प्रावधान नहीं है।

vi. सहमति समर्थित नहीं थी और प्रयोगकर्ताओं को काम अनियमित समय में करना पड़ता था।

vii. एनआईसी हार्डवेयर संसाधनों का भारी उपभोग।

viii. कुल 1099 केन्द्रीय विद्यालयों में से केवल 562 केन्द्रीय विद्यालयों में बायोमीट्रिक मशीनें वितरित की गई थीं।

ix. छात्रों को केवल 9969 ओएमवी कार्ड दिए गए थे जबकि छात्रों की संख्या 12 लाख से अधिक है।

(घ): शाला दर्पण के कार्यान्वयन में पेश आ रही समस्याओं के कारण यह परियोजना 1099 केन्द्रीय विद्यालयों तक सीमित है।

(ड.): जी हां। मध्य प्रदेश सरकार ने शाला दर्पण संबंधी प्रायोगिक परियोजना में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की है।

(च): जी नहीं।

******